दृष्टि The Vision

drishti

GENERAL STUDIES (Module – 4)

निर्धारित समय: तीन घंटे *Time allowed: Three Hours*	DTVF/19 (N-M)–M–**GS14**	अधिकतम अंक: 250 *Maximum Marks: 250*

Name: VIVESH **Mobile Number:**

Medium (English/Hindi): Hindi **Reg. Number:** Awate 19 F-11

Center & Date: M. Ngr. **UPSC Roll No.** ***(If allotted)*:** 0877016

प्रश्न-पत्र के लिये विशिष्ट अनुदेश

कृपया प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को ध्यानपूर्वक पढ़ें:

इसमें **बीस** प्रश्न हैं तथा हिन्दी और अंग्रेज़ी दोनों में छपे हैं।

सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने दिये गए हैं।

प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहियें जिसका उल्लेख आपके प्रवेश-पत्र में किया गया है, और इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यू.सी.ए.) पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिये। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिखे गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।

प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिये।

प्रश्न-सह-उत्तर-पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिये।

QUESTION PAPER SPECIFIC INSTRUCTIONS

Please read each of the following instruction carefully before attempting questions:

*There are **TWENTY** questions printed both in **HINDI** and **ENGLISH**.*

All the questions are compulsory.

The number of marks carried by a question is indicated against it.

Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate which must be stated clearly on the cover of this Question-cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in a medium other than the authorized one.

Word limit in questions, wherever specified, should be adhered to.

Any page or portion of the page left blank in the Question-cum-Answer Booklet must be clearly struck off.

केवल मूल्यांकनकर्त्ता द्वारा भरा जाए *(To be filled by Evaluator only)*

Question Number	Marks	Question Number	Marks
1.		11.	
2.		12.	
3.		13.	
4.		14.	
5.		15.	
6.		16.	
7.		17.	
8.		18.	
9.		19.	
10.		20.	
Grand Total (सकल योग)			

मूल्यांकनकर्त्ता (हस्ताक्षर)
Evaluator (Signature)

पुनरीक्षणकर्त्ता (हस्ताक्षर)
Reviewer (Signature)

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

1. भारत में सहकारी संघवाद के संबंध में कौन-से संवैधानिक प्रावधान हैं? साथ ही प्रतिस्पर्द्धी संघवाद को बढ़ावा देने के लिये नीति आयोग द्वारा हाल ही में किये गए कुछ उपायों पर भी चर्चा कीजिये। (150 शब्द) 10

What are the Constitutional provisions regarding cooperative federalism in India? Also discuss some of the recent measures taken by NITI Aayog to foster competitive federalism. (150 words) 10

भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। सशक्त केंद्र के साथ संघात्मकता के प्रावधान संविधान में किए गए हैं

विधायी शक्तियों का विभाजन

सातवीं अनुसूची
- राज्य सूची
- संघ सूची
- समवर्ती सूची

प्रशासनिक शक्तियों का विभाजन

संघ व राज्य की शक्तियों का भौगोलिक क्षेत्राधिकार

वित्तीय शक्तियां

* वित्त आयोग के माध्यम से वित्तीय बंटवारा
* सातवीं अनुसूची के तहत करारोपण की शक्तियों का विभाजन

प्रतिस्पर्धी संघवाद

यह अवधारणा राज्यों के भीतर प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर एक संतुलित केंद्रीय संघीय

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

संबंधों को स्थापित करती है

नीति आयोग द्वारा किए गए प्रयास

* साक्ष्य आधारित नीति निर्माण - एक थिंक टैंक के रूप में बाटम टू टॉप रणनीति के आधार पर नीति निर्धारण

* प्रतिस्पर्धी संकेतकों का विकास
  * राष्ट्रीय स्वास्थ्य सूचकांक
  * राष्ट्रीय शिक्षा सूचकांक

* नवाचार को प्रोत्साहित कर विकास
  अटल इनोवेशन मिशन

* निवेश को प्रोत्साहन
  ईज ऑफ डूइंग सूचकांक में सुधार हेतु प्रयास

भारत SDG लक्ष्यों की ओर अग्रसर है जिसे प्रतिस्पर्धी संघवाद के माध्यम से आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। इसमें नीति आयोग की भूमिका एक उत्प्रेरक की होगी।

2. सोशल मीडिया के युग में आदर्श आचार संहिता (एम.सी.सी.) का प्रवर्तन चुनौतीपूर्ण हो गया है। स्पष्ट कीजिये। इस संबंध में भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा किये गए कुछ उपायों का भी उल्लेख कीजिये। (150 शब्द) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

Enforcement of Model Code of Conduct (MCC) has become challenging in the era of social media. Elucidate. Also mention some of the measures taken by the Election Commission of India in this regard. (150 words) 10

आदर्श आचार संहिता एक नियमों तथा मानकों का समुच्चय है जिसे चुनाव के दौरान चुनाव आयोग लागू करता है ताकि निष्पक्ष चुनावों का आयोजन हो। सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव ने निम्न रूप से प्रभावित किया है-

* राजनीतिक दलों को प्रचार के विकल्पों का माध्यम मिला है। सोशल मीडिया प्लेटफार्म व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम ट्विटर।

* ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर नियंत्रण चुनौतीपूर्ण है क्योंकि → विज्ञापनों का नियमन ना होना

→ सूचना के स्रोत की पहचान मुश्किल

→ सर्वर प्राप्त मैना होकर विदेशों में

→ व्यापक लोगों तक पंहुच है साथ ही सूचनाओं का वेग अति तीव्र

drishtiias.com

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

* चुनाव आयोग के पास सोशल मीडिया को नियंत्रित करने के ना तो संसाधन उपलब्ध है और ना ही तकनीक

भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा उपाय

* मॉडल आदर्श आचार संहिता : सोशल मीडिया प्लेटफार्मों द्वारा स्वनियमन के तहत विकसित की गयी है जिसे इन चुनावों में शामिल किया गया।
* चुनाव को प्रभावित करने वाली सूचनाओं पर प्रतिबंध लगाना
* विज्ञापनों के व्यय को चुनावी व्यय में शामिल करना

सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को स्वनियमन के साथ-साथ निर्वाचन आयोग के सीमित हस्तक्षेप में लाकर तथा चुनावी सूचनाओं पर निगरानी रखकर इसके दुष्प्रभावों या विभेदकारी प्रभावों को कम किया जा सकता है

3. किन परिस्थितियों में एक विधायक को दल-बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित किया जा सकता है? क्या आप सहमत हैं कि इसके लाभप्रद परिणाम के अपेक्षाकृत दुष्प्रभाव अधिक हैं? (150 शब्द) 10

What are the circumstances under which a legislator can be disqualified under anti-defection law? Do you agree that it has caused more harm than good? (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

भारतीय संविधान में दसवीं अनुसूची के तहत दल-बदल के आधार पर विधायक को ~~किर~~ अयोग्य घोषित किया जा सकता है। इसे घोषित करने का अधिकार सदन के सभापति विधान सभा अध्यक्ष के पास होता है

परिस्थितियाँ जिनके आधार पर उम्मीदवार अयोग्य घोषित हो सकता है

* यदि विधायक ने किसी अन्य दल की सदस्यता ले ली हो
* 2/3 सदस्य यदि दल से अलग होते हैं तो इसे दल का विभाजन माना जाएगा इसे दल बदल के तहत अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा।
* यदि विधायक ने दल की व्हिप की पालना नहीं की हो
* मनोनीत सदस्य ने 6 माह के ~~पूर्व~~ पश्चात्

किसी राजनीतिक दल की सदस्यता लेली हो

विधानसभा अध्यक्ष को इस कानून के तहत छूट प्राप्त है

इस प्रावधान के लाभ एवं हानि

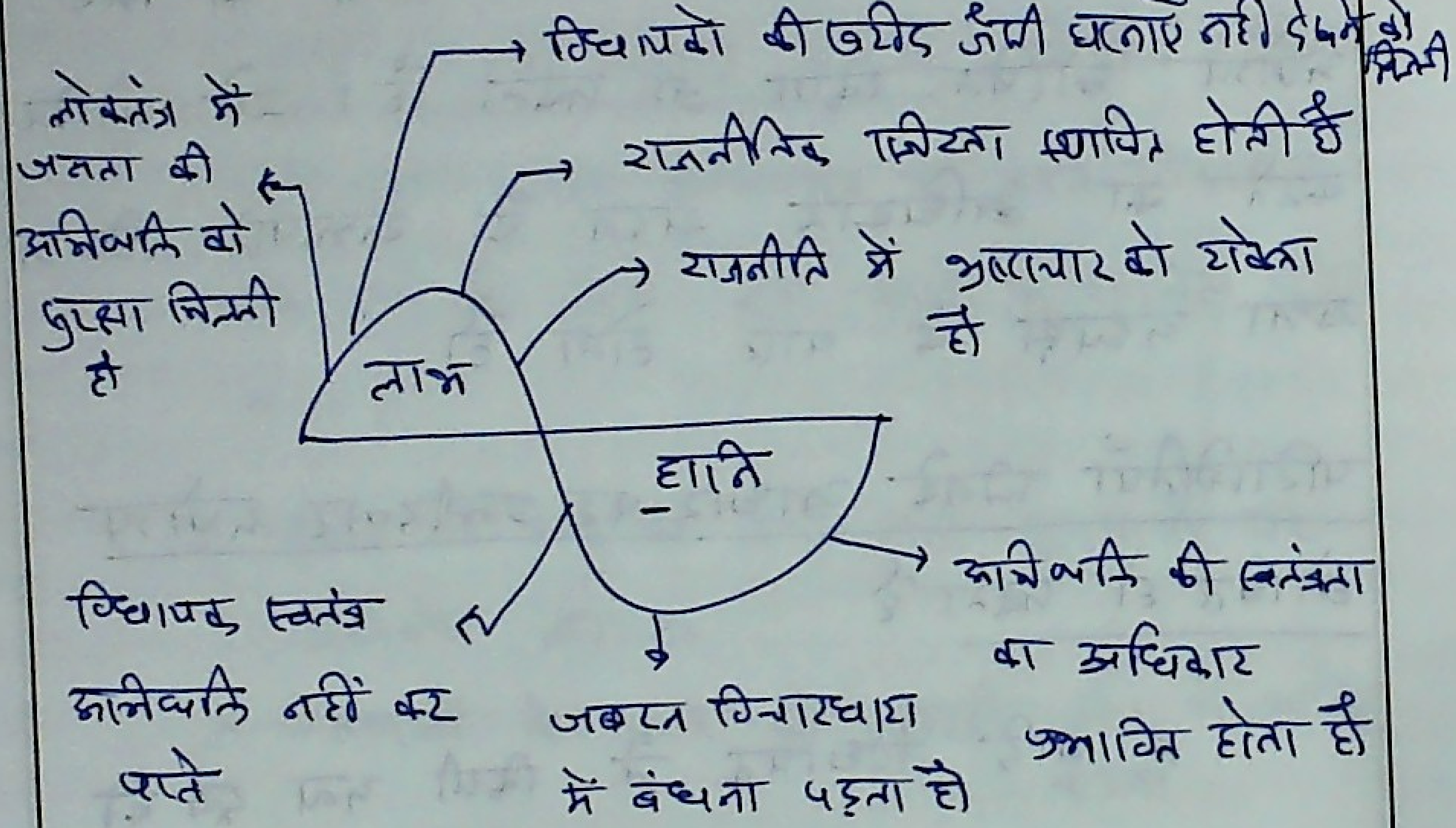

यद्यपि दल बदल कानून की कुछ हानियाँ है किंतु बदलते राजनीतिक परिदृश्य में इसे बनाए रखने की आवश्यकता है किंतु इसे सीमित एवं महत्वपूर्ण मुद्दों पर ही उपयोग में लाया जाए यथा

- विधानसभा अध्यक्ष के
- विश्वास मत की स्थिति में
- बजट पारित किए जाते
- महत्वपूर्ण विधेयकों पर

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

4. राष्ट्रपति और राज्यपालों के अध्यादेश लागू करने की शक्तियों से संबंधित विभिन्न मुद्दे क्या हैं? साथ ही अध्यादेश लागू करने की शक्ति के दुरुपयोग की रोकथाम हेतु संरक्षोपायों का उल्लेख कीजिये। (150 शब्द) 10

What are the various issues around ordinance making power of President and Governors? Also discuss the safeguards which are in place to prevent misuse of ordinance making power. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

भारतीय संविधान में अनुच्छेद 123 तथा अनुच्छेद 213 के तहत क्रमशः राष्ट्रपति व राज्यपाल को सदन सत्र में न रहने पर विशेष परिस्थिति में कार्यवाही करने हेतु अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गयी है

अध्यादेश जारी करने से संबंधित मुद्दे

* यह राज्यपाल व राष्ट्रपति की शक्ति न होकर कार्यपालिका की शक्ति है
* कार्यपालिका द्वारा विधायिका शक्तियों के विकल्प के रूप में उपयोग किया जाता है
* अध्यादेशों की भाषा बदल कर उसे बार-बार प्रख्यापित किया जाता है
* अध्यादेशों को पारित करते समय स्पष्ट कारणों को नहीं रखा जाता।
* दूसरे सदन में बहुमत न होने पर विकल्प के रूप में प्रयोग

www.drishtiias.com

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

सर्वोच्च न्यायालय ने अपने विभिन्न निर्णयों में अध्यादेश की शक्तियों पर अंकुश(?) लगाए हैं

* अध्यादेश जारी करने के आधारों की जांच न्यायिक पुनरीक्षण के अधीन
* अध्यादेश का उपयोग अंतिम विकल्प के रूप में किया जाना चाहिए।
* अध्यादेश को मात्र बदल कर पुर्नस्थापित करना गैर संवैधानिक
* अध्यादेश जारी करने के कारणों को सदन के समक्ष रखा जाना चाहिए।
* इसे सदन के पुनः सत्र में आते ही सदन पटल पर रखकर 6 सप्ताह में पारित किया जाना चाहिए।

अध्यादेश की शक्ति किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर अविलंबनीय रूप से कार्यवाही करने हेतु प्रदान की गई है। इसे विधायिका का विकल्प ना बनाते हुए मूल भावना के तहत उपयोग में लाना चाहिए।

5. लोकपाल के कर्त्तव्य और शक्तियाँ क्या हैं? क्या लोकपाल का पद सरकार और अन्य, जिनकी जाँच हेतु इसे आज्ञापित किया गया है, से स्वतंत्र है? (150 शब्द) 10

What are the duties and powers of Lokpal? Is the office of the Lokpal independent of the government and others whom it is mandated to scrutinise? (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

लोकपाल अधिनियम - 2018 के माध्यम से लोकपाल की केंद्र में स्थापना की गयी है।

कर्तव्य एंव शक्तियां

* अपने क्षेत्राधिकार के तहत भ्रष्टाचार की शिकायतों को सुनकर जाँच करना
* CBI को जांच के लिए नियुक्त किया जा सकता है। CBI पर अधीक्षण की शक्ति उन मामलों में प्राप्त होगी जिन्हें लोकपाल द्वारा सुपुर्द किया गया हो
* सिविल सेवकों (ग्रुप A, B, C, D कर्मचारियों) के दुर्व्यवहारो, गैर कानूनी कार्यों की अधीक्षण व जांच की शक्ति प्राप्त हो
* लोकपाल दोषी पाए जाने पर उचित दंड या सेवा से निष्कासन की संस्तुति कर सकता है
* इसे सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त है।

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लि[खना] चाहिये।
(Candidate must [not] write on this mar[gin])

लोकपाल पर सरकार और अन्य पर जांच हेतु कुछ सीमाएँ आरोपित की गयी हैं-

(i) प्रधानमंत्री के खिलाफ 2/3 सदस्यों की सहमति पर ही सुनवाई हो सकती है।

(ii) उच्च सिविल सेवकों पर जाँच तथा प्रारंभिक जाँच हेतु उनके नियुक्ति अधिकारी से अनुमति लेनी होगी।

(iii) लोकपाल को स्वतः संज्ञान के तहत जाँच करने की शक्ति नहीं दी गयी है।

लोकपाल को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की पालना तथा सिविल सेवकों की जवाबदेही बढ़ाने हेतु नियुक्त किया गया है। हालांकि इस पर कुछ सीमाएँ आरोपित की गयी हैं संरक्षणात्मक गैर तार्किक सीमाओं को दूर किए जाने की आवश्यकता है।

6. भारत में सुशासन के मार्ग में आने वाली कुछ प्रमुख बाधाओं को गिनाइये। इन बाधाओं को ध्यान में रखते हुए सुशासन के लिये आवश्यक पूर्व-शर्तों की विवेचना कीजिये। (150 शब्द) 10

Enumerate some of the key barriers to good governance in India. Taking cues from these barriers, discuss the necessary pre-conditions for good governance. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

बदलते परिदृश्य में विकास व शासन की गुणवत्ता सुधारने की नई अवधारणा सुशासन है जो चार स्तम्भों पर टिकी है।

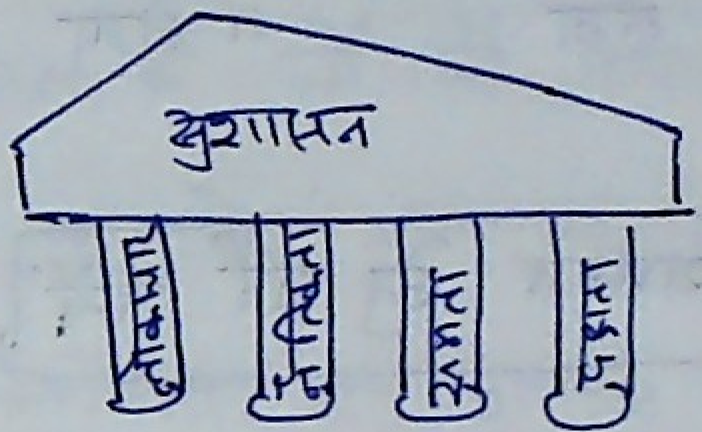

सुशासन के चार स्तम्भ

भारत के संदर्भ में सुशासन के मार्ग में बाधाएँ

(1) सिविल सेवकों की मनोवृत्ति

- औपनिवेशिक जड़ता
- गोपनीयता पर जोर
- मूल्यों में कमी
- प्रक्रिया-पर जोर
- प्रतिबद्धता का अभाव

(2) संरचनात्मक कमियाँ

- प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र की कमी
- एकल खिड़की व्यवस्था का ना होना
- मंत्रालयों में तालमेल का अभाव
- फीडबैक तंत्र नीतिगत तंत्र को प्रभावित करता है

www.drishtiias.com

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लि[खना] चाहिये। (Candidate must [not] write on this mar[gin])

③ विधायी बाधाएँ

- कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन न होना
- RTI के तहत स्व प्रकटीकरण न होना
- दोषियों पर कार्यवाही में देरी
- न्यायिक ढांचे की कमजोरी
- ICT का सीमित प्रयोग

सुशासन हेतु पूर्व शर्तें

* प्रभावी न्यायिक ढांचा
* कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रभावी संस्थागत व प्रशासनिक ढांचा
* सक्षम सिविल सेवक जिनमें सिविल सेवा मूल्यों की उपस्थिति हो
* राजनीतिक नैतिकता
    * राजनीति के अपराधीकरण में कमी
    * अन्तः दलीय लोकतंत्र
* शक्तियों का विकेंद्रीकरण।

इन सबके अतिरिक्त प्रभावी RTI कानून का क्रियान्वयन, एक दक्ष शिकायत निवारण तंत्र तथा सिटीजन चार्टर सुशासन के स्वप्न को साकार कर सकता है।

7. अनुच्छेद 370 की संवैधानिक स्थिति क्या है? वर्तमान परिदृश्य में इससे संबंधित मुद्दों और चुनौतियों पर चर्चा कीजिये। (150 शब्द) 10

What is the Constitutional status of Article 370? Discuss issues and challenges related to it in the current scenario. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

हाल ही में संसद द्वारा अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य के दर्जे को समाप्त कर दिया गया है। अब अनुच्छेद 370 खंड (1) के तहत जम्मू कश्मीर भारतीय केंद्र शासित प्रदेश है। साथ ही लद्दाख भी अलग केंद्र शासित प्रदेश है।

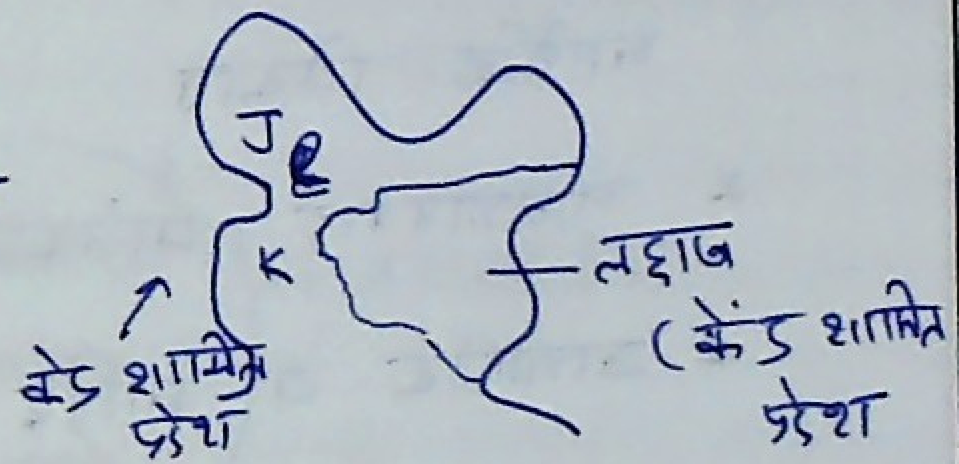

वर्तमान समय में 370 से संबंधित मुद्दे

* कानून की प्रक्रियात्मकता की स्वतंत्र जांच
* राज्यों के रूप में प्राप्त अधिकारों से जम्मू कश्मीर के निवासियों का वंचित रह जाना
* भौगोलिक विभाजन की व्यवहार्यता
* स्थानीय दृष्टिकोण, जनमत का शामिल न किया जाना

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

चुनौतियां

* भौगोलिक एकता को सांस्कृतिक एकता में रूपान्तरित करना
* कानून व्यवस्था व नागरिक अधिकारों को पुनर्स्थापित करना
* जम्मू कश्मीर में सुशासन, सरकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन कर आर्थिक विकास
* अलगाववाद, आतंकवाद को समाप्त करना
* सामाजिक व आर्थिक संकेतकों में सुधार।

राष्ट्रीय एकता व भौगोलिक एकता के संदर्भ में J&K का भारतीय संघ में समावेशन एक क्रांतिकारी कदम है हालांकि इसके नकारात्मक प्रभावों को कम कर भारत के प्रति स्थानीय लोगों में विश्वास पैदा किया जा सकता है

8. आपके अनुसार भारत में लोक सेवाओं को प्रभावित करने वाले प्रमुख विकार कौन-से हैं? क्या लोक सेवाओं में पार्श्व प्रवेश (लेटरल एंट्री) इनमें से कुछ विकारों का समाधान कर सकता है? (150 शब्द) 10

What do you think are some of the major ailments afflicting civil services in India? Can lateral entry in civil services address some of these ailments? (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

हाल ही में लेटरल एंट्री के माध्यम से सिविल सेवा में कुछ निजी क्षेत्र से व्यक्तियों को शामिल किया गया। यह सिविल ~~सेवाओं~~ सेवाओं में निम्न विकारों को दूर करने में मदद करेगा

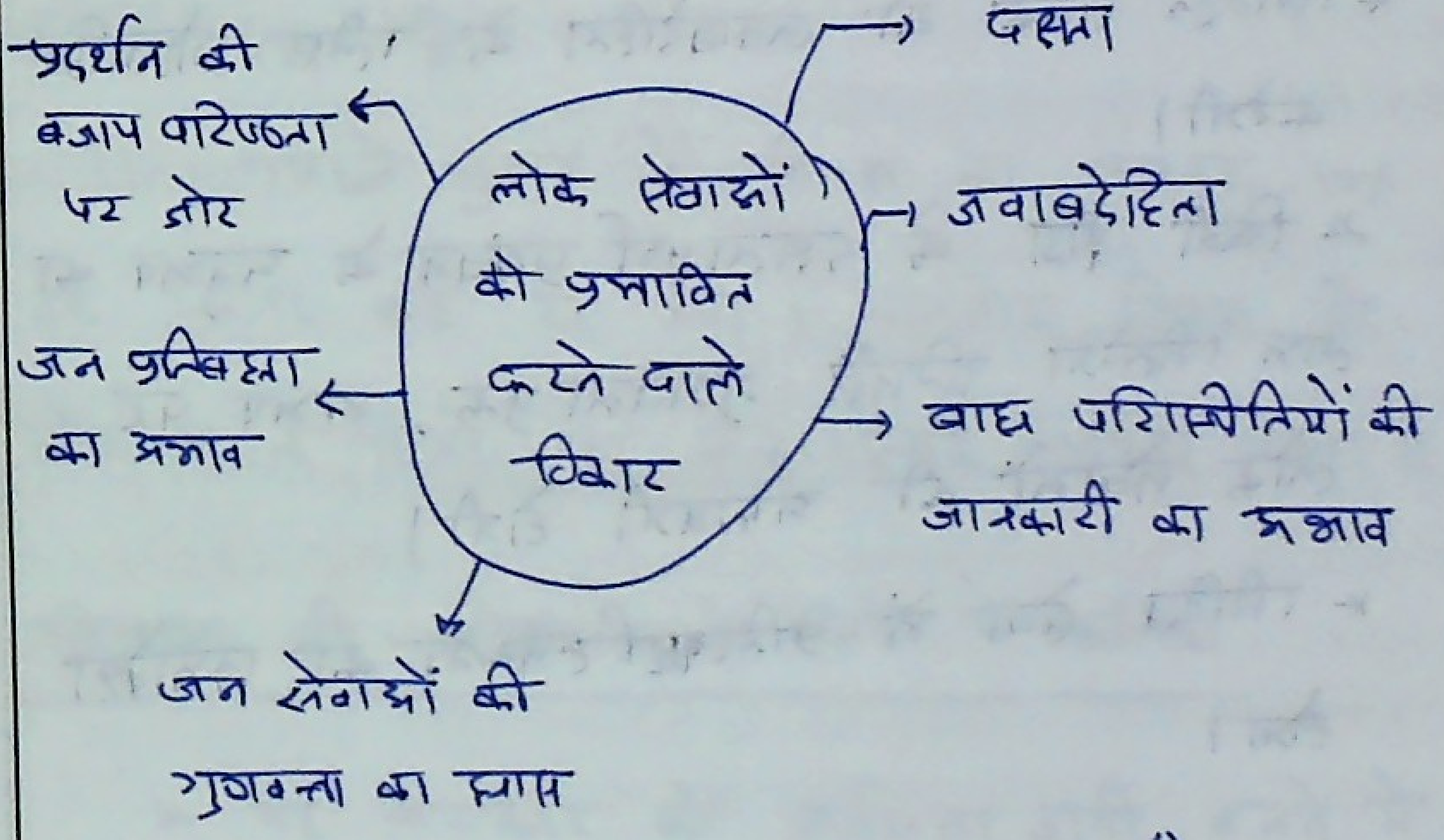

लेटरल एंट्री द्वारा इन विकारों को निम्न प्रकार से दूर किए जाने का प्रयास है -

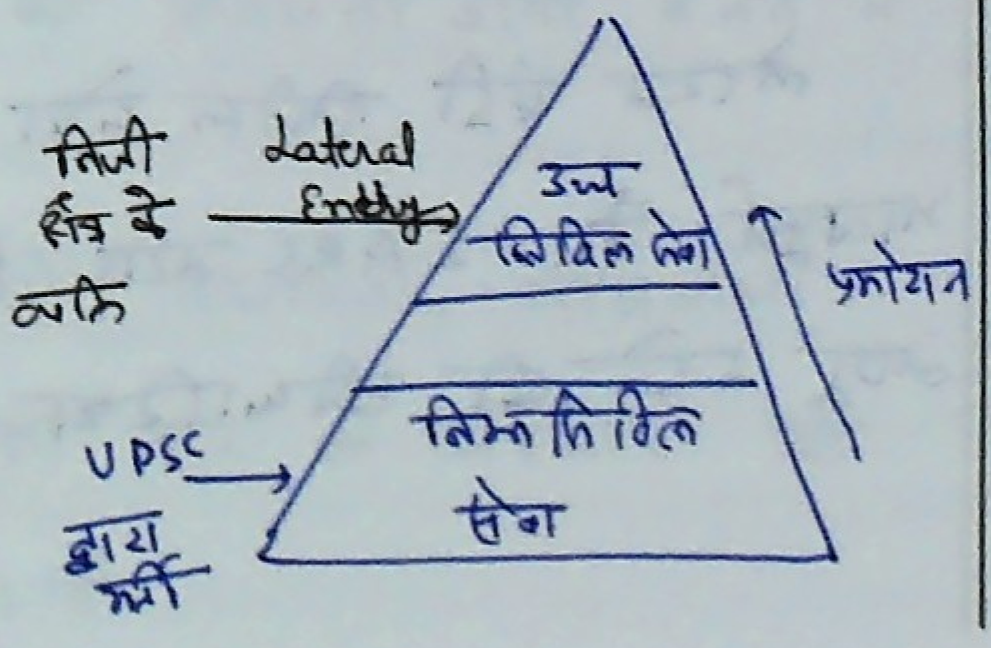

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

* यह नौकरशाही की जड़ता को दूर करेगी तथा सक्रिय करेगी।
* इससे सिविल सेवकों को बाह्य परिस्थितियों की जानकारी मिलेगी तथा नीति निर्माण में बेहतर इनपुट मिलेगें।
* नीति निर्माण में निजी क्षेत्र के दृष्टिकोण को शामिल करेगी - LPG के दौर में अत्यावश्यक
* सिविल सेवकों को जवाबदेहिता के लिए प्रोत्साहित करेगी।
* निजी क्षेत्र के दक्षतापूर्ण प्रबंधन के अनुभव का लाभ मिलेगा जिससे गुणवत्तायुक्त, समय पर लोक सेवाओं की अदायगी होगी।
* सिविल सेवा में प्रतिस्पर्धात्मकता का समावेश होगा।

लेटरल एंट्री सिविल सेवा सुधार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। 2nd ARC तथा विभिन्न आयोगों ने इसे लागू करने की सिफारिश की थी।

drishti | दृष्टि The Vision

9. एक कमज़ोर विपक्ष सत्ताधारी सरकार को तो खुश कर सकता है परंतु यह लोकतंत्र के हितों को नहीं साधता है। भारत में हालिया आम चुनावों के परिणाम के आलोक में इस कथन की विवेचना कीजिये।

(150 शब्द) 10

A weak opposition may make the government of the day happy but it does not serve the cause of democracy. Discuss the statement in light of the outcome of recent general elections in India.

(150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

सत्ताधारी दल के विधायी तथा कार्यपालिका निर्णयों की जवाबदेहिता सुनिश्चित करने में विपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है एक सशक्त लोकतंत्र में एक सशक्त विपक्ष की उपस्थिति अत्यावश्यक है

पिछले चुनाव में विपक्ष का आकार 10% तक सिमट कर रह गया। कमजोर विपक्ष से लोकतंत्र के हितों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है

विपक्ष की लोकतंत्र के हितों में भूमिका

* यह सरकार को सर्वसत्तावादी बनने से रोकता है
* सरकारी निर्णयों, विधायनों, योजनाओं आदि की समीक्षा कर सरकार को जवाबदेह बनाता है

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

* जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाता है
* सरकार को संवेदनशील मुद्दों पर जागृत कर कार्यवाही करने के लिए मजबूर करता है।
* सरकार द्वारा वित्तीय दुरुपयोग, घोटालों आदि का खुलासा करता है

कमजोर विपक्ष होने से देश इन सभी लाभों से वंचित हो जाता है। कमजोर विपक्ष लोकतंत्र के मूल्यों को कमजोर करता है विरोध, विपक्ष को अभिव्यक्ति नहीं मिलती है जो सरकारी उत्तरदायित्व को कम करती है अधिनायकवादी सत्ता के बनने की संभावना को बल मिलता है

drishti | दृष्टि The Vision

10. विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों (पी.वी.टी.जी.) के निर्धारण हेतु अनुपालित मानदंडों का उल्लेख कीजिये। उनके द्वारा किन मुद्दों का सामना किया जाता है? साथ ही इन मुद्दों के समाधान के लिये सरकार द्वारा किये गए उपायों का भी उल्लेख कीजिये। (150 शब्द) 10

State the criteria followed for the determination of Particularly Vulnerable Tribal Groups (PVTGs). What are the issues faced by them? Also mention the measures taken by the government to address these issues. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

ढेबर आयोग द्वारा संस्तुतित किए जाने के पश्चात्

सरकार ने 22 जनजातियों को PVTG के रूप

में पहचान की है

निर्धारण हेतु अनुपालित मापदंड

* पृथकतावादी उपस्थिति

भौगोलिक अलगाव
- A & N द्वीपसमूह
- लक्षद्वीप

सांस्कृतिक अलगाव
- अन्य समुदायों से जुड़ाव ना होना

* विकास की स्थिति निम्न

* आर्थिक व सामाजिक निम्न संकेतकों की उपस्थिति

* ऐतिहासिक सांस्कृतिक विलक्षणता

* ऐतिहासिक पृथकतावाद

* जनजातीयता

PVTG द्वारा सामना की जा रही चुनौतियाँ

चुनौतियाँ

- बाहरी हस्तक्षेप
  पर्यटन, जमींदारी व्यवस्था अन्य संस्थाएँ
  अन्य समुदायों के माध्यम से
- विकास की निम्न स्थिति
  - सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन ना होना
- कानूनों का अप्रभावी क्रियान्वयन
- आजीविका संबंधी अधिकार छिनना
  विकास बनाम विस्थापन में सर्वाधिक शिकार
- वन कानूनों, वनाधिकार, लघु उपज अधिकार कानूनों का अप्रभावी क्रियान्वयन

सरकार द्वारा किए गए उपाय

संवैधानिक
* मूल अधिकार
* DPSP
* पांचवीं व छठी अनुसूची के तहत सुरक्षा

विधायी
* वन कानून
* वनाधिकार कानून
* एट्रोसिटीज एक्ट
* जनजातीय सुरक्षा कानून

नीतिगत
- नेहरू जी की पंचशील नीति

योजना/कार्यक्रम
* जनजातीय उप योजना
* वन बंधु कल्याण योजना आदि

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लि... चाहिये।
(Candidate must ... write on this mar...

11. राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रारूप, 2019 भारत के शिक्षा क्षेत्र को एक नया आकार दे सकता है। समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये। (250 शब्द) 15

Draft National Education Policy, 2019 can give a new shape to India's education sector. Critically examine. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

भारतीय शिक्षा क्षेत्र में एक समग्र दृष्टि के साथ पर्याप्त सुधारों की आवश्यकता है जिसके लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति – 2019 का प्रारूप एक महत्वपूर्ण कदम है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रारूप – 2019 :

* यह शिक्षा को वहनीय तथा गुणवत्तायुक्त उपलब्ध कराने पर बल देता है

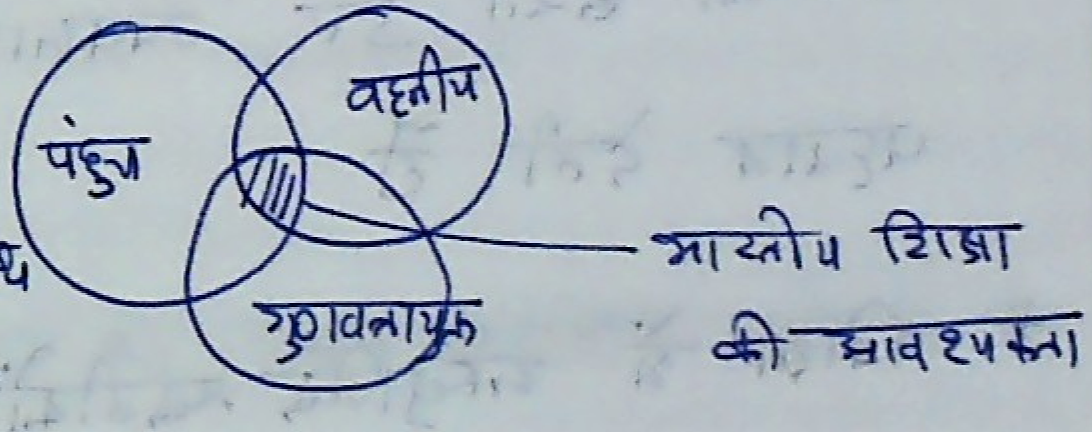

* स्कूली शिक्षा तथा विश्वविद्यालय शिक्षा के व्यवसायिक शिक्षा से जुड़ाव को लक्षित करता है

* शिक्षा में स्कूलों की भूमिका को स्वीकारता है

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लि[खना] चाहिये। (Candidate must [not] write on this mar[gin])

* शिक्षा के मानकों को केवल नामांकन से ऊपर जाते हुए अधिगम आधारित बनाने को लक्षित करता है।

* राष्ट्रीय शिक्षा नीति व्यवसाय परक, रोजगार आधारित, कौशल आधारित शिक्षा को मान्यता प्रदान करती है।

* पारंपरिक शिक्षा व व्यवसायिक शिक्षा को एकीकृत करते हुए व्यवसायिक शिक्षा को पहचान देती है।

* शिक्षा में आधुनिक तकनीकों को शामिल करने की आवश्यकता पर बल देती है।

* शिक्षक - छात्र अनुपात सुधार, अवसंरचनात्मक सुधार, शिक्षक गुणवत्ता पर बल देती है।

* शिक्षा में निजी क्षेत्र व विदेशी शिक्षण संस्थाओं की उपस्थिति को महत्वपूर्ण मानती है।

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

* शिक्षा को समावेशी बनाने का लक्ष्य घोषित करती है जिसमें दिव्यांगजनों को शामिल करती है

शिक्षा नीति की चुनौतियाँ

* अधिगम आधारित, परिणाम आधारित मूल्यांकन व्यवस्था के क्रियान्वयन का पक्ष सीमित
* स्कूलों में डिजिटल शिक्षा तथा तकनीकों के प्रयोग का तत्व अनुपस्थित

भारतीय शिक्षा को दिशा निर्देशित करने के लिए प्रारूप शिक्षा नीति समय की व भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होगी।

12. "सामाजिक अंकेक्षण परिकल्पना और वास्तविकता के बीच के अंतर को कम करने में सहायता प्रदान करता है।" इस कथन का परीक्षण कीजिये और भारत में सामाजिक अंकेक्षण को प्रणालीबद्ध करने में आने वाली बाधाओं पर भी चर्चा कीजिये। (250 शब्द) 15

"Social audit helps to narrow gaps between vision and reality." Examine the statement and also discuss the impediments in institutionalization of social audit in India. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

सामाजिक अंकेक्षण किसी कार्यक्रम, योजना, परियोजना के आकलन हेतु समाज (स्थानीय लोग, लाभार्थी, सिविल समाज) को शामिल करना है।

भारत में पहली बार मनरेगा के माध्यम से सामाजिक अंकेक्षण को लागू किया गया।

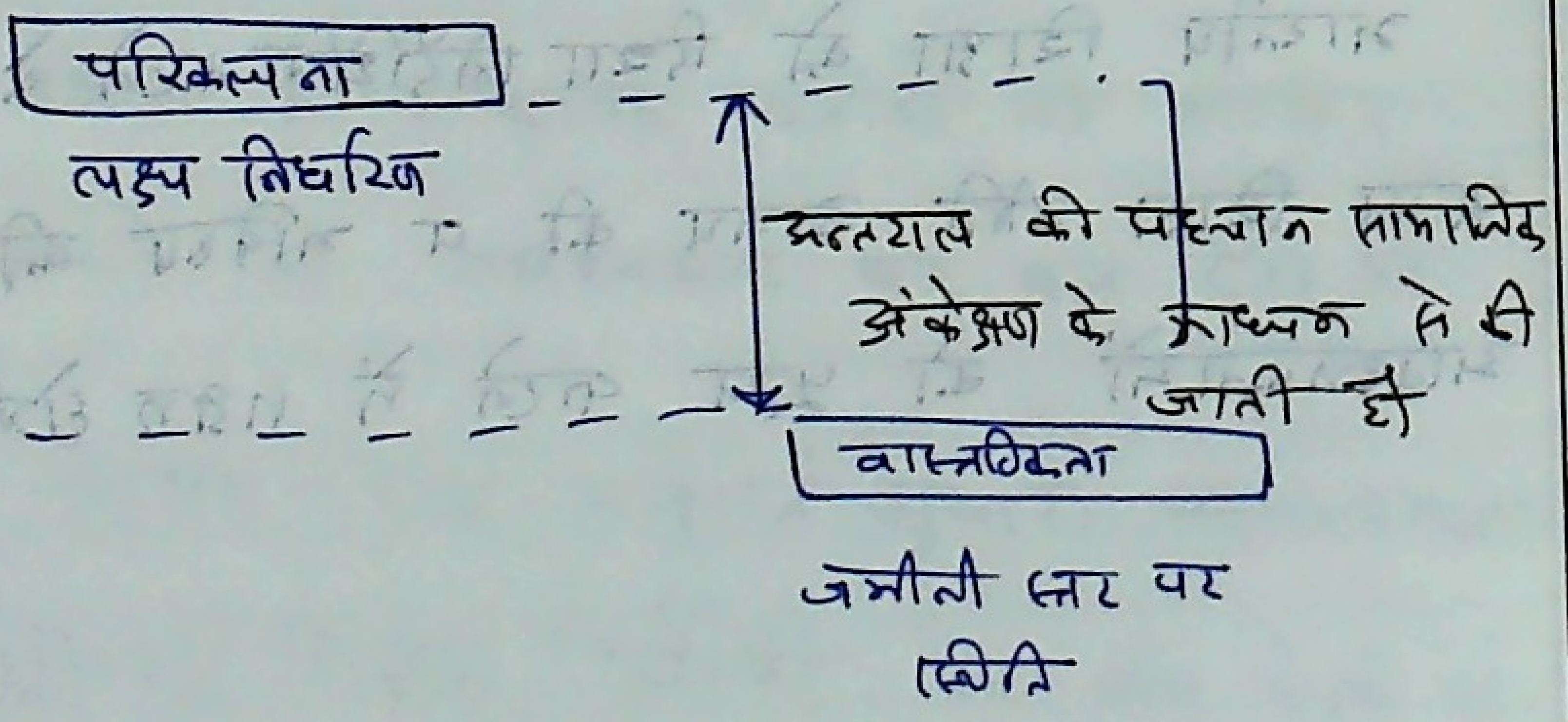

यह योजना क्रियान्वयन अधिकारियों तथा नीति निर्माताओं को जमीनी स्तर का वास्तविक

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

फीडबैक प्रस्तुत करता है

* इनपुट के तौर प्राप्त सूचनाओं को योजना/परियोजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रोत्साहक के रूप में प्रयोग लाया जाता है
* भविष्य नीति निर्माण में महत्वपूर्ण इनपुट के रूप में अंतराल को कम करने में मदद करता है
* यह सरकार को सीधे जनता से जोड़ता है इससे ना केवल सेवा अदायगी की गुणवत्ता में सुधार आता है बल्कि सहभागीपूर्ण भागीदारी से लोकतंत्र को मजबूती मिलती है।
* यह कागज स्तर पर निर्धारण को जमीनी वास्तविकता से जोड़ता है
* उदा॰ मनरेगा में लागू करने से मिले लाभ

लाभ
- योजना के मानकों में सुधार करना
- फर्जी लाभार्थियों की पहचान हुई
- आर्थिक संसाधनों का दुरुपयोग कम
- मध्यस्थों द्वारा भ्रष्टाचार की समाप्ति हुई

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

सामाजिक अंकेक्षण में बाधाएँ

* सामाजिक अंकेक्षण एक सीमित क्षेत्र को ही कवर करता है
* सामाजिक अंकेक्षण में स्थानीय जनता में जनजागरूकता का अभाव विद्यमान है
* जन भागीदारी के पर्याप्त प्लेटफार्मों व अवसंरचना का विकास नहीं किया गया है यथा ICT का सीमित उपयोग
* उपलब्ध डाटा की गुणवत्ता तथा प्रोसेसिंग एक महत्वपूर्ण चुनौती है
* विभागों में एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र की कमी है

लोकतंत्र, प्रशासन के दृष्टिकोण से सामाजिक अंकेक्षण एक प्रगतिशील अवधारणा है जो लोकतंत्र को सहभागीपूर्ण बनाती है। इसकी चुनौतियों को दूर कर इसे शीघ्र लागू किए जाने की अपेक्षा है।

13. 73वाँ संशोधन अधिनियम पंचायती राज संस्थाओं (पी.आर.आई.) के समक्ष आने वाली प्रणालीगत चुनौतियों को हल करने में नाकाम रहा है। समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द) 15

73rd Amendment Act has failed to address the systemic challenges faced by Panchayati Raj Institutions (PRIs). Critically analyse. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

भारतीय संविधान में 73 वें संविधान संशोधन के माध्यम से भाग 9 स्थापित कर पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देकर विकेंद्रीकरण का प्रयास किया गया।

PRI के समक्ष प्रणालीगत चुनौतियाँ

[1] वित्तीय चुनौती

* पर्याप्त वित्तीय स्रोतों का अभाव
* राज्यों द्वारा सीमित धन हस्तांतरण
* राज्य वित्त आयोग
  - गठन न किया जाना
  - सीमित शक्तियाँ
  - अनुशंसाओं पर सीमित चर्चा तथा कार्यान्वयन
* राज्य विधानमण्डलों द्वारा कराधान की शक्तियों का स्थानान्तरण न किया जाना
* स्वयं संस्थाओं द्वारा वित्त उगाही न कर पाना

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

कार्यात्मक चुनौतियाँ

- राज्य विधानमण्डलों द्वारा सीमित शक्तियों का स्थानान्तरण
- समय पर पर्याप्त अधिकारियों की उपलब्धता ना होना
- नियुक्ति के अधिकार न दिया जाना मानव संसाधन सीमितता की स्थिति है।

संस्थागत चुनौतियाँ

- संविधान के पांच वर्ष पर चुनावी बाध्यताओं को पूरा नहीं किया जाना
- राजनीतिक हस्तक्षेप राजनीतिक दलों की भूमिका
- मॉनिटरिंग तथा अनुश्रवण तंत्र का अभाव

इन चुनौतियों के कारण PRI की उत्पादकता अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंच पायी है

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

PRI द्वारा सकारात्मक प्रभाव

* निर्णय निर्माण का विकेन्द्रीकरण हुआ है
* सामाजिक अंकेक्षण हेतु आधार तैयार हुआ है
* महिलाओं के प्रतिनिधित्व में सुधार

43% प्रतिनिधि महिलाएँ
- शिक्षा स्वास्थ्य मानकों में सुधार
- सार्वजनिक वित्त का सदुपयोग
- महिला समस्याओं को प्राथमिकता तथा महिला सशक्तिकरण

* बॉटम टू टॉप नीति निर्माण की आधारशिला प्राप्त हुई है

लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की दिशा में PRI का अस्तित्व एक महत्वपूर्ण कड़ी है इन्हें पर्याप्त कार्यात्मक, वित्तीय स्वायत्तता प्रदान कर इनकी अपेक्षित सफलता प्राप्त हो सकती है

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

14. किसी लोकतंत्र में एक स्वतंत्र और जवाबदेह न्यायपालिका नागरिकों के अधिकारों का सर्वोत्तम संरक्षोपाय है। परीक्षण कीजिये। (250 शब्द) 15

An independent and accountable judiciary is the best safeguard of citizens' rights in a democracy. Examine. (250 words) 15

भारतीय नागरिकों, संविधान के संरक्षण हेतु न्यायपालिका को शासन के तीन अंगों के रूप में स्थापित किया है।

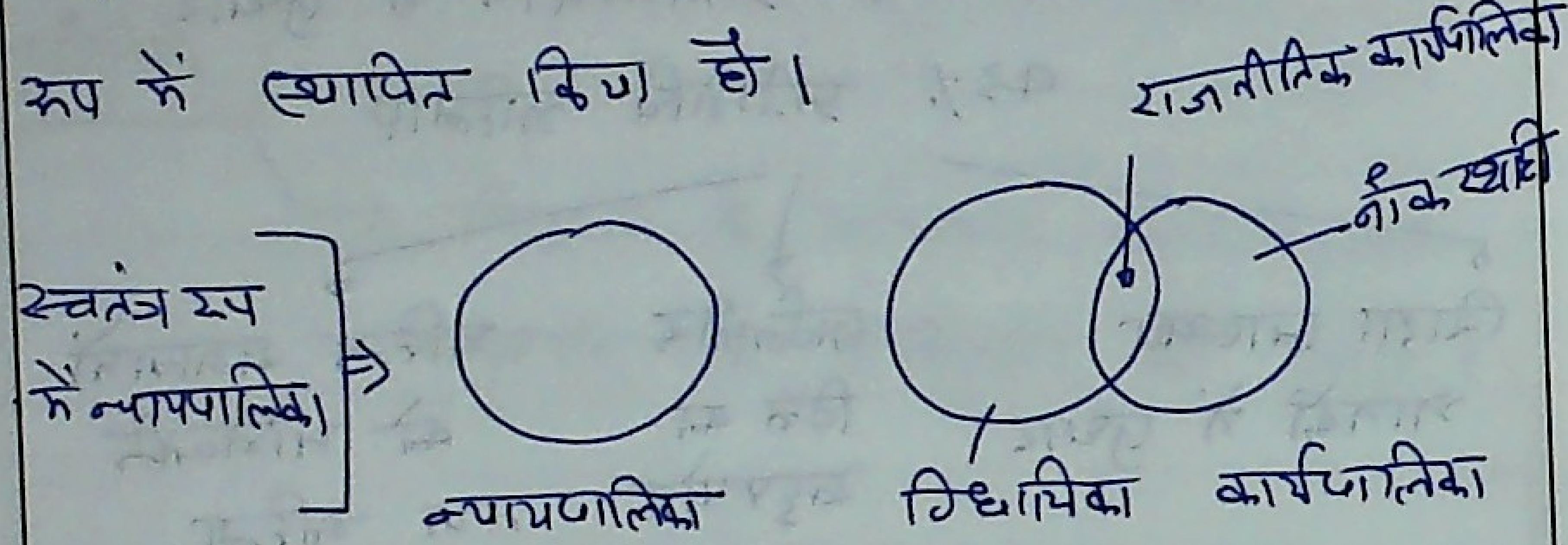

लोकतंत्र में स्वतंत्र न्यायपालिका की भूमिका

* यह राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त रहती है जिससे न्यायपालिका का लक्ष्य जन हित होता है
* व्यापक रूप में जनता के अधिकारों की रक्षा करती है। उदा० न्यायपालिका द्वारा दिए गए निर्णय → पर्यावरणीय अधिकार

विशाखा गाइडलाइन
मजदूरों के आजीविका अधिकार

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

हालांकि न्यायिक स्वतंत्रता निम्न चुनौतियाँ भी प्रस्तुत करती है

- न्यायिक सक्रियता वाद
  शक्तियों के पृथक्करण को असंतुलित करती है
- नियुक्ति संबंधी पारदर्शिता
  - अंकल जज सिंड्रोम
- न्यायिक जवाबदेहिता की चुनौती

जवाबदेह न्यायपालिका की लोकतंत्र में भूमिका

* न्यायपालिका की जवाबदेहिता न्यायिक तंत्र में जनता के विश्वास को स्थापित करती है
* न्याय की अवधारणा में गुणवत्ता का समावेश करती है।
* न्यायपालिका की जवाबदेहिता समावेशी लोकतंत्र का उदाहरण प्रस्तुत करती है

उदाहरण

- तीसरे लिंग के रूप में ट्रांसजेंडर्स के अधिकार
  नालसा बनाम भारत संघ
- IPC 377 को गैर संवैधानिक घोषित कर LGBT समुदायों की रक्षा
- RTI की धारा 66 (A) के संबंध में निर्णय देकर आलोचकों के अधिकार की रक्षा

drishti दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

न्यायिक जवाबदेही की चुनौतियाँ

* महाभियोग जैसी एकमात्र जवाबदेही प्रक्रिया एक कठिन प्रक्रिया
* आन्तरिक अनुशासनात्मक व्यवस्था की प्रणाली की कमी
* RTI जैसी सुविधाओं का लागू न होना
* राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की असंवैधानिकता जवाबदेहिता को प्रश्न करती है।
* लंबित मामलों की बढ़ती संख्या
  - 3 करोड़ से अधिक मामले लंबित

लोकतांत्रिक व्यवस्था में न्यायपालिका जनता के अधिकारों की रक्षक है अतएव इसे पर्याप्त स्वतंत्रता मिलनी चाहिए लेकिन यह जवाबदेहिता के बिना संभव नहीं है। न्यायपालिका की जवाबदेहिता निश्चित रूप से जनता तथा संविधान के प्रति होनी चाहिए।

15. स्वयं सहायता समूह गरीबों को सूक्ष्म वित्त सेवाओं के वितरण के लिये सबसे प्रभावी तंत्र के रूप में उभरे हैं। समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये। (250 शब्द) 15

Self-Help Groups have emerged as the most effective mechanism for delivery of microfinance services to the poor. Critically examine. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

स्वंय सहायता समूह कुछ व्यक्तियों का समूह होता है जो वित्तीय ऋण आदि आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु एकजुट होते है। भारत में सूक्ष्म वित्त सेवाओं के वितरण हेतु इन समूहों का उपयोग किया जाता है।

स्वंय सहायता समूह एक प्रभावी तंत्र के रूप में

* व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की बजाय सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना वितरण की गुणवत्ता को बढ़ाता है।
* सामूहिक उत्तरदायित्व ऋण की सुभेद्यता को कम करता है जिससे वित्तीय संस्थानों पर बोझ कम होता है
* एक इकाई के रूप में व्यवसायिक व वित्तीय लाभ प्राप्त करना आसान होता है

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

* स्वंय सहायता समूहों ने सामुदायिकता को सुदृढ़ करने में भूमिका निभाई है जिससे

सामाजिक संकेतकों - शिक्षा, स्वास्थ्य, लैंगिक समानता

आर्थिक संकेतकों - गरीबी, आय, असमानता

में सुधार हुआ है

* महिलाओं की स्थिति में सुधार आया है
* पारंपरिक ज्ञान को रोजगार में बदलने के अवसर प्राप्त हुए हैं।

स्वंय सहायता समूहों की चुनौतियाँ

* यद्यपि सूक्ष्म वित्त सेवाओं पर उपलब्धता है जिससे रोजगार सृजन हुआ है किंतु

- तकनीक
- कौशल अभाव
- उत्पादों की गुणवत्ता
- मानकीकृत उत्पाद

के अभाव की समस्या अभी भी बनी हुई है

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

* उत्पाद वैश्विक प्रतिस्पर्धी नहीं हैं। निर्यात क्षमता का उपयोग नहीं किया जा सका है
* बड़े वित्तीय संस्थानों द्वारा अभी भी ऋण देने में हिचक बनी हुई है

सरकारी प्रयासों यथा मुद्रा योजना, कौशल विकास योजनाओं, रोजगार योजनाओं (प्रधानमंत्री आजीविका मिशन योजना) आदि में ईकाई के रूप में स्वंय सहायता समूहों की उपस्थिति इनके बेहतर प्रबंधन की मांग को उत्प्रेरित करती है

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लि
चाहिये।
(Candidate must
write on this mar

16. भारत जैसे देश में आर्थिक प्रगति और राजनीतिक स्थिरता के लिये संतुलित क्षेत्रीय विकास अति आवश्यक है। 'आकांक्षी ज़िलों के परिवर्तन' कार्यक्रम के आलोक में इस कथन की विवेचना कीजिये। (250 शब्द) 15

Balanced regional development is quite essential for economic progress and political stability in a country like India. Discuss the statement in light of 'Transformation of Aspirational Districts' programme. (250 words) 15

यद्यपि भारत आर्थिक संकेतकों में सुधार के माध्यम से आर्थिक प्रगति की राह पर है किंतु क्षेत्रीय असमानता अभी भी एक चुनौती है।

आर्थिक प्रगति हेतु संतुलित क्षेत्रीय विकास की आवश्यकता

* यह असमानता को कम करता है
  Ex. देश की 90% संपत्ति जनसंख्या के 3% के पास
* यह समावेशी विकास के SDG लक्ष्यों के अनुरूप है जिससे SDG लक्ष्यों।
  - गरीबी उन्मूलन
  - भुखमरी उन्मूलन
  - शिशु मृत्युदर मातृ मृत्युदर आदि में कमी
  - सबके लिए स्वास्थ्य शिक्षा

  को प्राप्त करना आसान होगा।

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

* यह संवैधानिक आर्थिक न्याय के मूल्य को स्थापित करती है

राजनीतिक स्थिरता हेतु संतुलित क्षेत्रीय विकास-

* यह क्षेत्रीयता के रूप में अलगाववादी मांगों को रोकने में सहायक है यथा महाराष्ट्र में विदर्भ की मांग, उत्तर प्रदेश में हरित प्रदेश की मांग
* राष्ट्रीय एकता व अखंडता के लिए आवश्यक है
* नक्सलवाद जैसी चरमपंथी विचारधाराओं के विकास को रोकती है

इन्हीं चुनौतियों को दूर करने के लिए देश के सर्वाधिक पिछड़े जिलों को शामिल कर आकांक्षी जिलों का परिवर्तन लक्ष्य रखा गया है। इसमें 28 राज्यों से 115 जिलों को लक्षित किया गया है

आकांक्षी जिलों में पांच प्रमुख बिंदुओं पर कार्य किया जाएगा

1. स्वास्थ्य व पोषण
2. शिक्षा
3. वित्तीय समावेशन
4. कौशल विकास
5. कृषि, जल संसाधन + अवसंरचना

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517

उम्मीदवार को इ
हाशिये में नहीं
चाहिये।
(Candidate mus
write on this m

* यह कार्यक्रम प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देगा
* विकास की गतिविधियों को वास्तविक समय के आधार पर दर्ज किया जाएगा
* 49 संकेतकों के माध्यम से जिलों के मानकों व विकास पर नजर रखी जाएगी।
* सरकारी योजनाओं व कार्यक्रमों को

सहयोग — समन्वय — अभिसरण।

के माध्यम से लक्षित कर सुधार किया जाएगा।

आकांक्षी जिला परिवर्तन देश के क्षेत्रीय रूप से सर्वाधिक पिछड़े जिलों को लक्षित कर आर्थिक असमानता को कम करने के प्रयास है जिससे राजनीतिक स्थिरता आएगी। भारत के आर्थिक विकास के साथ साथ राष्ट्रीय एकता व अखंडता भी सुनिश्चित होगी

17. शंघाई सहयोग संगठन (एस.सी.ओ.) भारत की 'कनेक्ट सेंट्रल एशिया' नीति को आगे बढ़ाने का एक संभावित मंच है। चर्चा कीजिये। (250 शब्द) 15

Shanghai Cooperation Organization (SCO) is a potential platform to advance India's 'Connect Central Asia' policy. Discuss. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

शंघाई सहयोग संगठन एक सहयोग, आर्थिक विकास तथा सुरक्षा हेतु संगठन है जिसमें भारत, रूस, चीन तथा पाकिस्तान के साथ मध्य एशियाई देश शामिल है।

कनेक्ट सेंट्रल एशिया नीति भारत की ऊर्जा सुरक्षा, भौगोलिक सुरक्षा, आर्थिक विकास तथा सांस्कृतिक जुड़ाव हेतु मध्य एशिया से जुड़ने की एक नीति है।

मध्य एशिया के पांच देशों

1) कजाकिस्तान
ii) किर्गिस्तान
iii) ताजिकिस्तान
iv) उज्बेकिस्तान
v) तुर्कमेनिस्तान

— (i)–(iv) में से 4 शंघाई सहयोग परिषद के सदस्य हैं।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

* भारत का एकमात्र विदेशी सैन्य अड्डा ताजिकिस्तान में स्थित है।

* कजाकिस्तान में विश्व का सर्वाधिक यूरेनियम है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा हेतु महत्वपूर्ण है

भारत की कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी को आगे बढ़ाने में SCO एक मंच के रूप में

* भारत सीमा पार आतंकवाद से प्रभावित रहा है। भारत अपनी सुरक्षा के लिए मध्य एशिया से जुड़ना चाहता है SCO के उद्देश्यों में अलगाववादी तत्वों, आतंकवाद की समाप्ति शामिल है।

* यह सेंट्रल एशिया में भारत-चीन प्रतिस्पर्द्धा को कम करके सहयोगात्मकता को शामिल करेगा।

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

* चीन की BRI, OROB (वन रोड वन बेल्ट) पहलों में भारतीय चिंताओं को व्यक्त करेगा जिसका मध्य एशिया एक हिस्सा है

* BRI के प्रत्युत्तर में भारत द्वारा प्रस्तावित INSTC (अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण गलियारे) को पूरा करने में महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करेगा।

* चाबहार के माध्यम से मध्य एशिया से जुड़ाव को आसान बनाएगा

* यह मध्य एशिया तथा अन्य देशों को अफगानिस्तान की स्थिरता हेतु प्रयास करने के लिए प्रेरित करेगा।

मध्य एशिया से जुड़ाव भारत के लिए दीर्घकालिक रूप से आर्थिक, सांस्कृतिक राजनैतिक लाभ हासिल करेगा जिसकी सफलता हेतु शंघाई सहयोग परिषद् एक महत्वपूर्ण मंच है

18. दक्षिण एशिया में सहयोग को बढ़ाने में सार्क की विफलता ने क्षेत्रीय देशों को बिम्सटेक के रूप में एक व्यावहारिक विकल्प तलाशने हेतु प्रेरित किया है। परीक्षण कीजिये। (250 शब्द) 15

The failure of SAARC to nurture cooperation in South Asia has pushed regional players to explore BIMSTEC as a viable alternative. Examine. (250 words) 15

उम्मीदवार को इ… हाशिये में नहीं … चाहिये। (Candidate mu… write on this m…

बदलते भूराजनीतिक समीकरणों, व्यापार परिदृश्यों में क्षेत्रीय सहयोग एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में उभरा है। SAARC तथा BIMSTEC दक्षिण एशिया में इसी सहयोग की अभिव्यक्ति है।

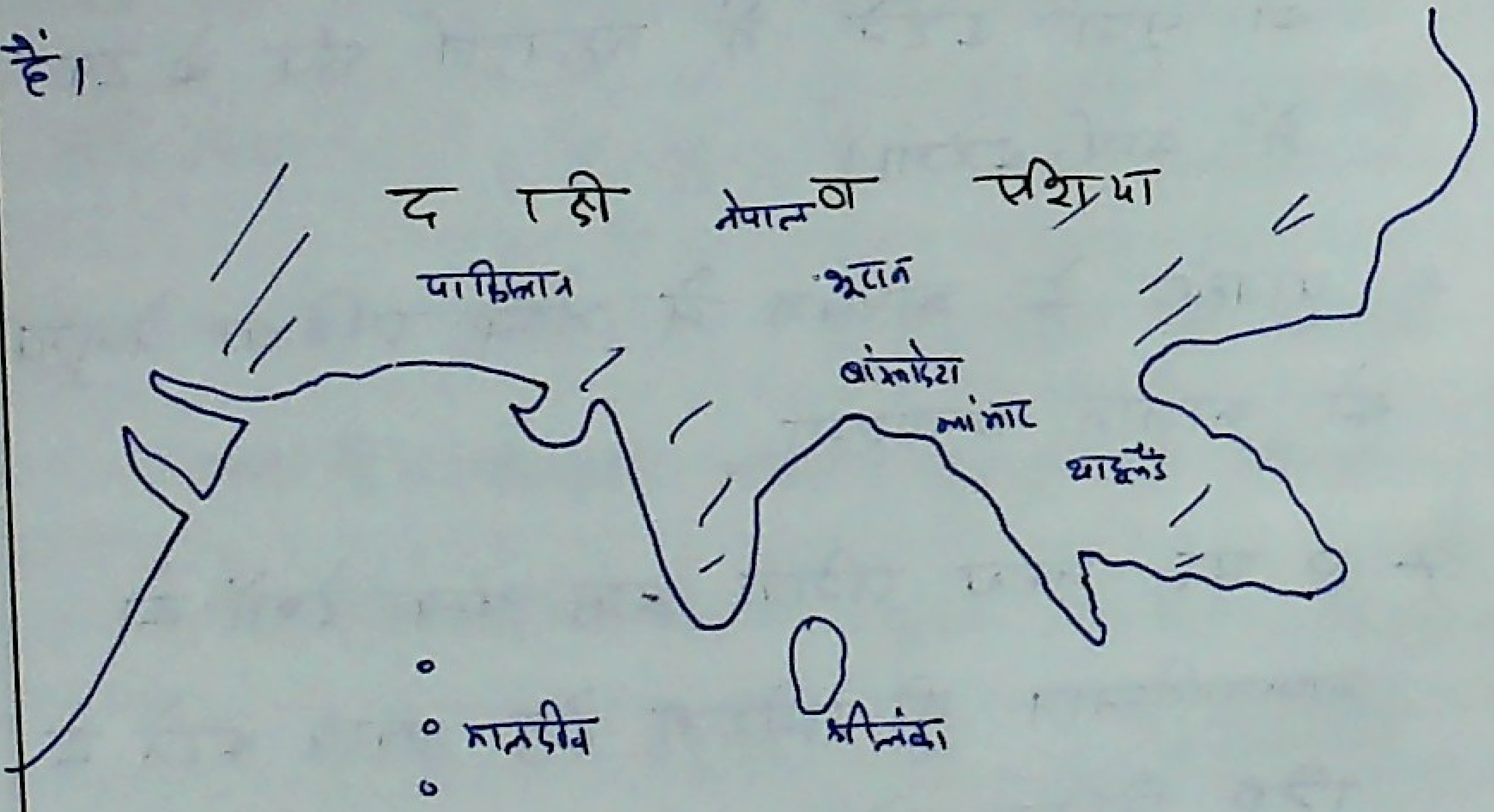

सार्क देश

* भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान अफगानिस्तान, मालदीव, बांग्लादेश

BIMSTEC देश -

* भूटान, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल बांग्लादेश, थाईलैंड

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिख[illegible] चाहिये।
(Candidate must no[illegible] write on this margi[illegible]

SAARC की सीमितताएँ

* इसमें थाईलैंड, म्यांमार शामिल नहीं थे जबकि ये भारत के कनेक्टिविटी के हित जुड़े हैं।
* सार्क में पाकिस्तान की उपस्थिति ने निकाय निर्णयों में एकमत स्थापित करने में चुनौती प्रस्तुत की है।
* सार्क के सम्मेलनों की विफलता (राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के कारण) विकास प्रक्रिया को अवरुद्ध करती है। पिछला सम्मेलन 2014 में

BIMSTEC एक विकल्प के रूप में

* पाकिस्तान की अनुपस्थिति ने अवांछित विरोध को कम किया है
* थाईलैंड व म्यांमार की उपस्थिति ने इस मंच को व्यापकता दी है
* बिम्सटेक SAARC व ASEAN का सेतु के रूप में स्थापित हुआ है

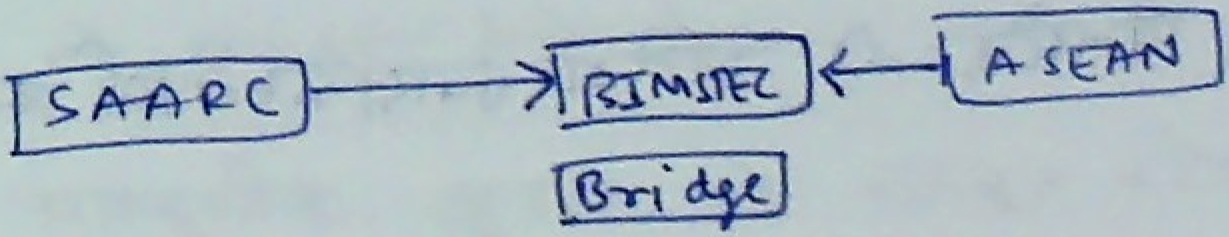

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार क
हाशिये में न
चाहिये।
(Candidate
write on thi

* बढ़ता व्यापार BIMSTEC की व्यवहार्यता को बढ़ाता है।
* उत्तरपूर्व के विकास हेतु दक्षिणी एशिया से कनेक्टिविटी हेतु BIMSTEC महत्वपूर्ण मंच
  सितवे बंदरगाह उत्तर पूर्व में कोलकाता की तुलना में अधिक पास
* आसियान से जुड़ने के 2025 के लक्ष्य हेतु बिम्सटेक एक मंच के रूप में
* भारत की त्रिपक्षीय राजमार्ग परियोजना भारत - म्यांमार - थाइलैंड के लिए उपयुक्त मंच
* भारत पूर्व की ओर देखो नीति से एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर स्थानांतरित हो चुका है इस प्रक्रिया में BIMSTEC महत्वपूर्ण

यद्यपि क्षेत्रीय संगठनों के रूप में सार्क व बिम्सटेक दोनों महत्वपूर्ण किंतु भौगोलिक जुड़ाव, आसियान भागीदारी तथा व्यापार, संस्कृति के लिए बिम्सटेक की भूमिका ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है

19. भारत के लिये क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (आर.सी.ई.पी.) का क्या महत्त्व है? विशेष रूप से चीन के साथ मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिये इसके निहितार्थ का परीक्षण कीजिये। (250 शब्द) 15

What is the significance of Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) for India? Examine its implications for the Indian economy especially in the context of free trade agreement with China. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

आर सी. ई. पी. आसियान + 6 देशों (भारत, चीन, जापान, कोरिया, आस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड) के मध्य मुक्त व्यापार समझौता है

RCEP का महत्व

* ~~...~~. आसियान देशों का भारत के साथ व्यापार ~~...~~ 1990 के बाद से काफी बढ़ा है।
* 1977 - 2016 में ASEAN से भारत में निवेश 70 बिलियन डॉलर था।
* एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत पूर्वोत्तर भारत के विकास हेतु
* भारतीय पर्यटन उद्योग, फार्मा उद्योग आदि को बढ़ावा देने हेतु
* सांस्कृतिक जुड़ाव को मजबूत करेगा।

उम्मीदवार को हाशिये में नह चाहिये। (Candidate write on this

चूंकि RCEP के सदस्य के रूप में चीन भी शामिल है अतएव चीन के साथ मुक्त व्यापार की स्थापना होगी जो निम्न चुनौतियाँ प्रस्तुत करेगा

* चीन के साथ मुक्त व्यापार की अवस्था में आयात शुल्कों की समाप्ति होगी जिससे चीनी सस्ते माल की भारतीय बाजारों में मुक्त उपस्थिति होगी।

* चीनी वस्तुओं की निम्न कीमत भारतीय उद्योगों को गैर प्रतिस्पर्धी बनाएगा।

* घरेलू बाजार व उत्पादक अत्यधिक प्रभावित होंगे।

* भारत चीन व्यापार घाटे को बढ़ाएगा जिससे भुगतान संतुलन पर भी दबाव बढ़ेगा

* भारत का निर्यात भी प्रभावित होगा चीनी वस्तुओं की उपस्थिति अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय वस्तुओं को प्रतिस्थापित करेंगी।

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

भारत को चीन के परिपेक्ष्य में लाभ

* वर्तमान व्यवस्था के तहत भारतीय वस्तुओं की चीन में उपस्थिति नगण्य है। भारत को चीन का बाजार उपलब्ध होगा।
* भारत का फार्मा उद्योग जेनेरिक दवायों के माध्यम से चीन में लाभ ले सकता है
* टेक्सटाइल, चमड़ा, ज्वैलरी उद्योगों को इसका लाभ होगा।
* IT कम्पनियों के लिए चीन में व्यवसायकेन्द्र होगा।

यद्यपि RCEP भारत के लिए अति लाभकारी है किंतु चीन की उपस्थिति कुछ चुनौतियाँ प्रस्तुत करती हैं। भारत अपने उत्पादों की गुणवत्ता तथा कीमत को प्रतिस्पर्द्धी बनाकर इसका लाभ ले सकता है।

20. निरंतर हठधर्मिता दिखाते चीन के साथ संबंधों को बनाए रखना भारतीय विदेश नीति की प्रमुख चुनौतियों में से एक के रूप में उभरा है। दक्षिण एशियाई क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव के संदर्भ में चर्चा कीजिये। (250 शब्द) 15

Dealing with an increasingly assertive China has emerged as one of the principal challenges of Indian foreign policy. Discuss in the context of China's growing influence in South Asian region. (250 words) 15

उम्मीदवार हाशिये में ... चाहिये। (Candidat... write on ...)

1962 के भारत-चीन युद्ध के पश्चात् भारत चीन संबंधों में गिरावट आयी है। हालांकि व्यापारिक उभार के बाद व्यवसायिक संबंधों में सुधार हुआ है परन्तु चीन के साथ संबंध चुनौतीपूर्ण ही बने हुए हैं जिसके निम्न प्रमुख कारण हैं-

* चीन द्वारा की जाने वाली गतिविधियाँ-

    * स्ट्रिंग ऑफ पर्ल

    भारत के पड़ोसी देशों में अपनी व्यापारिक व व्यवसायिक उपस्थिति के माध्यम से भारत को घेरने की नीति भारत के चीन के प्रति विश्वास को कमजोर करती है

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लि... चाहिये।
(Candidate must ... write on this ma...

* नदी जल विवाद

ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन द्वारा एकतरफा रूप से परियोजनाओं का संचालन किया जाना तथा डेटा उपलब्ध ना किया कराया जाना

* सीमा-विवाद

अक्साई चीन, अरूणाचल सीमा विवाद इस अविश्वास को बढ़ाते है हाल ही में इसी पृष्ठभूमि में डोकलाम विवाद हुआ

* व्यापार

* द्विपक्षीय व्यापार चीन के प्रति झुका हुआ है साथ ही चीनी उत्पादों पर सास्ती घरेलू बाजार को प्रभावित करती है
* चीनी उत्पादों की भारत में डंपिंग
* फार्मा, टेक्सटाइल क्षेत्रकों का चीन द्वारा न खोला जाना

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार
हाशिये में
चाहिये।
(Candidat
write on t

दक्षिण एशिया में चीन की बढ़ती उपस्थिति

* नेपाल, भूटान, बांग्लादेश को चेक बुक डिप्लो-मेसी के तहत प्रभावित करने का प्रयास
* बांग्लादेश - चितगांग, म्यांमार - सितवे, श्रीलंका - हम्बनटोटा के माध्यम से हिंद महासागर में अपनी उपस्थिति बढ़ा रहा है
* बेल्ट एंड रोड इनिशियेटिव में शामिल होने के लिए दक्षिणी एशियाई देशों पर दबाव बढ़ा रहा है

भारत और चीन दोनों उभरती अर्थव्यवस्थाएं हैं दोनों की प्रतिस्पर्धा आर्थिक, राजनैतिक व भूराजनैतिक स्तर पर व्यक्त होती है दीर्घकालिक लाभों के मद्देनजर भारत को विदेश नीति में चीनी संबंधों को व्यवहारिक परिप्रेक्ष्य में देखकर संतुलित बनाना होगा।